- अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ
- भारतीय अर्थव्यवस्था है विकासशील
- तृतीय विश्व (थर्ड-वर्ल्ड) शब्द प्रयुक्त होता
 है विकासशील देश के संदर्भ में
- विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका
- विश्व की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था चीन
- सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में स्थान- 5वाँ
- क्रय शक्ति-समता (PPP) के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में स्थान - तीसरा
- पूँजीवादी एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाला पहला देश - क्रमश : अमेरिका व रूस
- पूँजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत- एड्म स्मिथ की पुस्तक 'द वेल्थ ऑफ नेशंस'
- पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण होती है - पूर्ति और माँग द्वारा
- 'रखो और निकलो' नीति है पूँजीवाद की
- समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन किया
 धा जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने
- पूँजीवादी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण होता है
 निजी व्यक्तियों का
- समाजवादी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण होता है
 सरकार का
- मिश्रित अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण होता है
 निजी व्यक्ति एवं सरकार दोनों का
- भारत में अर्थव्यवस्था है मिश्रित
- मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है- निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व
- मिश्रित अर्थव्यवस्था का सुझाव दिया था
 अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड किंस ने
- मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का पहला देश है - फ्रांस
- मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रारंभ 1948 में
- बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ है
 आयात-निर्यात दोनों बंद
- मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किया -
- 1990 में अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने
 → मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है संयुक्त
- राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP), 1990 से
- मानव विकास सूचकांक (HDI) का आकलन का आधार है - जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर एवं प्रति व्यक्ति आय
- भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट (HDR)
 जारी की गई थी अप्रैल, 2002 में
- भारत के मानव विकास रिपोर्ट को कौन प्रकाशित या जारी करता है- नीति आयोग
- राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य - मध्य प्रदेश
- HDR-2020 के अनुसार मानव विकास मामले में भारत का स्थान - 131वाँ (189 देशों में)
- मानव विकास सूचकांक-2020 के अनुसार मानव विकास मामले में प्रथम तथा ऑतम स्थान पर हैं- क्रमशः नार्वे तथा नाइजीरिया

भारतीय अर्थव्यवस्था

- आर्थिक गतिविधियों के आधार पर अर्थव्यवस्था
 को तीन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र
- प्राथमिक क्षेत्र संबंधित है कृषि, पशुपालन, खनन, वानिकी, मत्स्यपालन से
- द्वितीयक क्षेत्र संबंधित है

 -विनिर्माण, निर्माण, विद्युत, जलपूर्ति से
- तृतीयक क्षेत्र संबंधित है सेवा क्षेत्र, चिकित्सा, परिवहन, शिक्षा, बैंकिंग, बीमा, होटल से
- सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र (कृषि),
 द्वितीयक क्षेत्र (उद्योग) एवं तृतीयक क्षेत्र (सेवा)
 का योगदान- 16.38%, 29.34% तथा 54.27%
- सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी
 1867-68 में दादा भाई नौरोजी द्वारा और प्रति व्यक्ति आय 20 रू. बताया था
- दादाभाई नौरोजी के पुस्तक को नाम है -Poverty and Unbritish Rule in India
- ⁴धन-निष्कासन' सिद्धांत को प्रतिपादित किया
 दादाभाई नौरोजी ने
- वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की गई - 1931-32 में, वी. के. आर. वी. राव द्वारा (प्रति व्यक्ति आय-62 रू.)
- स्वतंत्रता पश्चात् भारत सरकार द्वारा 'राष्ट्रीय आय समिति' का गठन - 4 अगस्त, 1949 को पी.सी. महालनोबिस की अध्यक्षता में
- राष्ट्रीय आय का सबसे पहला सरकारी अनुमान दिया - वाणिज्य मंत्रालय ने, 1948-49 में
- वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना करता है -केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (CSO)
- केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना हुई थी
 2 मई, 1951 को (मुख्यालय-नई दिल्ली)
- राष्ट्रीय आय की गणना में केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय की मदद करता है - राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (NSSO)
- राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता माना जाता है - साइमन कुजनेट्स को
- राष्ट्रीय आय है एक प्रवाह, स्टॉक नहीं।
- एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी समानों और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग कहलाता है - राष्ट्रीय आय
- राष्ट्रीय आय का सर्वश्रेष्ठ मापक है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (NNP)
- राष्ट्रीय आय निकालने के लिए NNP में से घटाया जाता है - अप्रत्यक्ष कर
- ♦ हिन्दू वृद्धि दर संबंधित है- राष्ट्रीय आय से
- हिन्दू वृद्धि दर के अवधारणा के प्रतिपादक थे
 प्रो॰ राज कृष्ण (1981) '
- वर्तमान में राष्ट्रीय आय गणना का आधार-वर्ष है - 2011-12
- भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है - तृतीयक क्षेत्र (सेवा क्षेत्र)

- भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है - प्राथमिक क्षेत्र (कृषि)
- अर्थव्यवस्था का वृद्धि दर मापा जाता है -राष्ट्रीय आय के अनुसार
- किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है - सकल घरेलू उत्पाद (GDP)
- िकसी देश की घरेलू सीमा में एक वित्तीय वर्ष में ऑतम वस्तुओं एवं सेवाओं से अर्जित कुल आय कहलाता है -सकल घरेलू उत्पाद (GDP)
- सकल राष्ट्रीय अत्पाद में से पूँजीगत वस्तुओं
 के मूल्य द्वास को घटा देने पर प्राप्त प्रतिफल कहलाता है - निबल राष्ट्रीय उत्पाद (NNP)
 - भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देने वाला राज्य है - महाराष्ट्र
- राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी कहलाता है श्वेत-पत्र
- ♦ राष्ट्रीय आय के संबंध में पहला श्वेत-पत्र जारी किया था - CSO ने 1956 में
- 'भारतीय सांख्यिकीय संस्थान' है-कोलकता में
- िकसी भी देश की आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक होती है - प्रति व्यक्ति आय
- प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है
 राष्ट्रीय आय में जनसंख्या से भाग देकर
- ♦ सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य गोवा
- न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य -विहार
- वर्तमान में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला केन्द्रशासित राज्य है - दिल्ली
- गरीबी से आशय है जीवन की 'आधारभूत आवश्यकताओं' की पूर्ति से वंचित रहना
- भारत में गरीबी का मापन का आधार है
 न्युनतम कैलोरी उपभोग व्यय
- भारत में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए प्रति व्यक्ति कैलोरी ग्राह्मता निर्धारित की गई है - क्रमशः 2400 कैलोरी एवं 2100 कैलोरी
- मूल्य स्तर के आधार पर गरीबी रेखा के निर्धारण का प्रस्ताव किया गया - 1989 में गठित लकड्वाला समिति द्वारा
- सुरेश तेंदुलकर सिमिति (2004) व सी. रंगराजन सिमिति (2012) संबंधित है -गरीबी निर्धारण
- भारत में निर्धानता रेखा के निर्धारण का पहला प्रयास किया - योजना आयोग ने 1962 में
- वर्तमान में भारत में निर्धानता रेखा या गरीबी
 रेखा का निर्धारण करता है नीति आयोग
- लॉरेंज वक्र है व्यक्तियों के आय वितरण का चित्रीय प्रदर्शन
- गिनी गुणांक है आय के वितरण की विषमता की माप की सबसे प्रचलित विधि
- विश्व बैंक द्वारा गरीबी रेखा निर्धारण मानक माना गया है -1.25 डॉलर प्रतिदिन आय को
- भारत में गरीबी निवारण के लिए सर्वप्रथम अपनाया गया - अंत्योदय कार्यक्रम (1978)
- अंत्योदय अन्न योजना की शुरूआत 25 दिसम्बर 2000 को, राजस्थान से (अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा)

- अन्तपूर्णा योजना की शुरूआत 25 अक्टूबर 2000 को, गजियाबाद के सिखोडा ग्राम से
- भारत में बेरोजगारी के आकड़ें जारी करता है
 राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO)
- अदृश्य/प्रच्छन/छिपी हुई बेरोजगारी मुख्य रूप से पाई जाती है - कृषि क्षेत्र में
- भारत में बेरोजगारी का स्वरूप है- संरचनात्मक
- संरचनात्मक बेरोजगारी होती है- दीर्घकालीन
- व्यवसायिक गतिविधि में एक समान मंदी से उत्पन्न बेरोजगारी कहलाती है - चक्कीय
- चक्रीय बेरोजगारी ज्यादा देखने को मिलती है
 विकसित देशों में
- ग्रामीण क्षेत्रों में पायी जाने वाली बेरोजगारी है
 मौसमी और अदृश्य/प्रच्छन बेरोजगारी
- शहरी क्षेत्रों में पायी जाने वाली बेरोजगारी है
 खुली /प्रत्यक्ष बेरोजगारी
- भगवती समिति संबंधित है बेरोजगारी से
- रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला पहला राज्य है - महाराष्ट्र
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (NREGA) की शुरूआत - 2 फरवरी, 2006 को, आंध-प्रदेश के अनंतपुर जिले से
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना पूरे देश में लागू की गई - 1 फरवरी, 2008 से
- + 'नरेगा' का नाम परिवर्तित कर 'मनरेगा' (महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) किया गया - 2 अक्टूबर, 2009
- मनरेगा का लक्ष्य है 100 दिनों की रोजगार
- सभी जिलों में '100 दिन की रोजगार गारंटी योजना' लागू करने वाला प्रथम राज्य - बिहार
- भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था - 2 अक्टूबर, 1952 को
- वित्तीय वर्ष की अविध -1 अप्रैल से 31 मार्च
- प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में
- वित्त आयोग का गठन होता है → राष्ट्रपित द्वारा (अनुच्छेद-280 (1) के तहत)
- राज्य वित्त आयोग का गठन-अनु,-243 (झ)
- वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष के.सी. नियोगी
- वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति- राष्ट्रपति
- वित्त आयोग का कार्यकाल होता है- 5 वर्ष
- वित्त आयोग में सदस्यों की संख्या होती है
 5 (अध्यक्ष सिंहत)
- 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष -वाई. वी. रेड्डी
- 15वें वित्त आयोग की अविध 2020-25
- 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह
- वित्त आयोग का मुख्य कार्य है केन्द्र तथा राज्य के बीच राजस्व का बँटवारा करना
- ७ वं वेतन आयोग का गठन फरवरी, 2014
- 7वें वेतन आयोग,अध्यक्ष-अशोक कुमार माथुर
- योजना आयोग द्वारां इंडिया विजन-2020 का दस्तावेज प्रस्तुत किया गया-23 जनवरी, 2003 को, श्यामा प्रसाद गुप्ता की अध्यक्षता में
- भारत में योजना का स्वरूप है मिश्रित

- भारत में सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन से संबंधित विचार दिया-एम. विश्वेश्वरैया ने 1934 में
- भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था (Planned Economy for India) पुस्तक को लिखा है
 एम. विश्वेश्वरैया ने (1934 में)
- 'भारत के आधुनिक नियोजन का प्रणेता' कहा जाता है- एम. विश्वेश्वरैया को
- 'गांधी योजना' को तैयार किया था
 श्री मन्नारायण ने (1944 में)
- 'बॉम्बे प्लान' (15वर्षीय योजना) लागू हुआ
 1944 में (8 उद्योगपितयों द्वारा)
- जन योजना (People's Plan) निर्मित की गई
 श्री एम॰ एन॰ राय द्वारा अप्रैल 1945 में
- सर्वोदय योजना को प्रस्तुत किया था -जयप्रकाश नारायण ने (जनवरी, 1950 में)
- राष्ट्रीय योजना सिमिति की स्थापना 1938 में
- राष्ट्रीय योजना सिमिति के अध्यक्ष थे
 पं॰ जवाहर लाल नेहरू
- राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट प्रकाशित हुई
 थी 1949 में
- योजना आयोग का गठन 15 मार्च, 1950
- योजना आयोग संस्था थी गैर-संवैधानिक
- 🔷 योजना आयोग का अध्यक्ष होता था प्रधानमंत्री
- योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष थे - क्रमशः पं॰ जवाहर लाल नेहरू तथा गुलजारी लाल नंदा
- योजना आयोग के ऑतम अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष थे - क्रमशः नरेन्द्र मोदी तथा मोंटेक सिंह अहलूवालिया
- योजना आयोग के स्थान पर किस नई संस्था का गठन हुआ - नीति आयोग (NITI-National Institution for Transforming India)
- नीति आयोग (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान)
 अस्तित्व में आई 1 जनवरी, 2015 को
- नीति आयोग के अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री
- पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है – नीति आयोग की
- नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष है
 क्रमणः नरेन्द्र मोदी एवं अरविन्द पनगढ़िया
- नीति आयोग संस्था है गैर-संवैधानिक एवं परामर्शदात्री संस्था
- पंचवर्षीय योजना के प्रारूप का अनुमोदन तथा
 ऑतिम स्वीकृति प्रदान करता है राष्ट्रीय
 विकास परिषद्
- राष्ट्रीय विकास परिषद् (NDC) का गठन हुआ था − 6 अगस्त, 1952 को
- ♦ NDC का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री
- 'सुपर कैबिनेट' के रूप में किसे जाना जाता है
 राष्ट्रीय विकास परिषद् (NDC)
- ♦ NDC संस्था है गैर-संवैधानिक
- राष्ट्रीय विकास परिषद् का पदेन सचिव होता
 है नीति आयोग का सचिव
- नियोजन से तात्पर्य है आर्थिक नियोजन
- नियोजन को सर्वप्रथम अपनाया रूस

- आर्थिक नियोजन विषय है- समवर्ती सूची में
- आर्थिक नियोजन संबंधित है-7वीं अनुसूची से
- नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ- 1951
- भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वयन का दायित्व होता है- केन्द्र और राज्य सरकार पर
- भारत में पंचवर्षीय योजनाएँ प्रेरित है- रूस से
- प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-56) आधारित थी - हैराड-डोमर मॉडल पर
- प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था
 कृषि विकास
- द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956-61) आधारित
 थी पी॰सी॰ महालनोविस के मॉडल पर
- द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई
 भारी एवं आधारभूत उद्योगों को
- राउरकेला (उड़ीसा), भिलाई (छतीसगढ़) व दुर्गापुर (प॰वंगाल) इस्पात कारखानों की स्थापना की गई - दूसरी योजना काल में
- तृतीय पंचवर्षीय योजना (1961-66) आघारित थी-सैंडी, चक्रवर्ती, महालनोविस मॉडल पर
- तृतीय पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई
 अर्थव्यवस्था को आत्म निभंर बनाने पर
- अबतक की सबसे असफल योजना तृतीय
- तृतीय योजना का विकास दर लक्ष्य एवं प्राप्ति दर लक्ष्य था - क्रमशः 5.6% तथा 2.8%
- ♦ तृतीय पंचवर्षीय योजना के असफलता का कारण था - भारत-पाक युद्ध (1965), भारत-चीन युद्ध (1962) एवं भयंकर अकाल
- 1964 में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी - तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में
- तीन वार्षिक योजनाओं को संज्ञा दी जाती है
 योजना अवकाश (1966-69) की
- 🔷 योजना अवकाश की अवधि थी 1966-69
- चतुर्थ योजना की अविध थी 1969-74
- चतुर्थ पंचवर्षीय योजना आधारित थी
 डी॰ आर॰ गॉडगिल मॉडल पर
- गॉडिंगल योजना कहलाता है चतुर्थ योजना
- चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था
 स्थिरता के साथ आर्थिक विकास
- 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था
 चतुर्थ योजना काल में, 1969 में
- भारत में सर्वप्रथम परिवार नियोजन कार्यक्रम
 शुरू किया गया था 1952 में
- पाँचवी योजना का काल था 1974-78
- भाँचवी पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसने तैयार किया था - डी॰ पी॰ घर ने
- पाँचवी योजना का मुख्य उद्देश्य था निर्धनता उन्मूलन एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता
- चार वर्ष की पंचवर्षीय योजना थी पाँचवी (एक वर्ष पूर्व समाप्त कर दिया गया था)
- इंदिरा गांधी द्वारा 'गरीबी हटाओ' तथा 'निर्धनता उन्मूलन' का नारा दिया गया था - पाँचवी पंचवर्षीय योजना काल में
- 'काम के बदले अनाज' (1977-78) कार्यक्रम शुरू हुआ था - पाँचवी योजना काल में

- 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा 20-सूत्री कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ- पाँचवी योजना काल में
- 2 अक्टूबर, 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई - पाँचवी योजना काल में
- 1974 में राष्ट्रीय न्यूनत्तम आवश्यकता कार्यक्रम (NMNP) लागू हुआ था - पाँचवी योजना में
- 'अनवरत योजना' (रौलिंग प्लान) का काल था - 1978-80 (पाँचवी योजना के बाद)
- 'अनवरत योजना' देन है- गुन्नार मिर्डल की
- 'अनवरत योजना' के प्रतिपादक रेगनर फ्रिश
- 'अनवरत योजना' आधारित थी
- गांधीवादी मॉडल पर
- नाबार्ड की स्थापना (12 जुलाई, 1982) हुई थी - छठी योजना काल (1980-85) में शिवरामन समिति के सिफारिश पर
- छठी योजना (1980-85) आधारित थी -आगत-निर्गत मॉडल पर
- छठी योजना का मुख्य उद्देश्य था रोजगार सुजन तथा गरीबी निवारण
- बेरोजगारी उन्मूलन से संबंधति IRDP, NREP, TRYSEM, DWACRA, RLEGP कार्यक्रम लागू की गई थी - छठी योजना में
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना प्रारंभ हुई थी - छठी योजना काल में
- सातवीं योजना की अवधि थी 1985-90
- इॅरिरा आवास योजना (1985-86) तथा जवाहर रोजगार योजना (28 अप्रैल, 1989) का प्रारंभ - सातवीं योजना काल में
- नेहरू रोजगार योजना (अक्टूबर, 1989) प्रारंभ - सातवीं योजना काल में
- आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) की मॉडल तैयार की थी- जॉन डब्लू मिलर ने
- आठवीं योजना का मुख्य उद्देश्य था
- मानव संसाधन का विकास
- आठवीं योजना का विकास दर लक्ष्य एवं प्राप्ति दर लक्ष्य था - 5.6% तथा 6.8%
- महिला संवृद्धि योजना (2 अक्टूबर, 1993) का प्रारंभ हुआ था - 8 वीं योजना काल में
- प्रधानमंत्री रोजगार योजना (15 अगस्त, 1993) की शुरूआत हुई - आठवीं योजना काल में
- आगत-निर्गत मॉडल पर आधारित नौवीं योजना (1997-2002) का उद्देश्य था - सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक विकास
- दसवीं योजना का काल था 2002-2007
- दसवीं योजना का मुख्य उद्देश्य था देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना
- अबतक की सबसे सफल एवं सबसे विकास दर वाली योजना थी - दसवीं योजना
- दसवीं योजना का विकास दर लक्ष्य एवं प्राप्ति लक्ष्य था - क्रमश: 8% तथा 7.6%
- 11वीं योजना की अवधि थी 2007-2012
- 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था - तीव और समावेशी विकास
- 12वीं योजना की अवधि थी 2012-2017

- 12वीं योजना का मुख्य उद्देश्य था तीव, संपोषणीय और अधिक समावेशी विकास
- 12वीं योजना में आर्थिक वृद्धि दर लक्ष्य एवं प्राप्ति लक्ष्य था - क्रमश: 8% तथा 7.6%
- 'योजना' पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है - सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा
- आर्थिक सुधार नीतियों का शुभारंभ -1991 में
- नई आर्थिक नीति (1991) के दौरान भारत के वित्त मंत्री कौन थे - मनमोहन सिंह
- आर्थिक क्षेत्र में उदारीकरण के एक नए युग की शुरूआत हुई - 1991 से
- भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है - मनमोहन सिंह को
- TRYSEM (ग्रामीण युवाओं हेतु स्वरोजगार प्रशिक्षण) योजना की शुरूआत हुई थी - 15 अगस्त, 1979 को
- ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्य - 1982 में (DWCRA) प्रारंभ हुआ था
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (NREP) की - 1980 में शुरूआत हुई थी
- सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (SGRY) का शुभारंभ हुआ था- 25 सितम्बर, 2001 को
- जवाहर ग्राम संवृद्धि योजना का आरंभ हुआ था - 1 अप्रैल, 1999 में
- 'सर्वशिक्षा अभियान' तथा 'प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना' की शुरूआत - 2000-01 में
- जल प्रबंधन से संबंधित 'हरियाली योजना' का शुभारंभ - 27 जनवरी, 2003 को
- कृषक बीमा आय योजना प्रारंभ 2003-04
- 'स्व-जलधारा कार्यक्रम' प्रारंभ- दिस. 2002
- 'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना' प्रारंभ की गई - दिसम्बर, 2000 को
- इंदिरा आवास योजना प्रारंभ 1985-86 में
- 'प्रधानमंत्री रोजगार सूजन कार्यक्रम' फ्रारंभ किए गए - 15 अगस्त, 2008 से
- 'कपार्ट' का गठन हुआ था 1 सितम्बर, 1986 को (मुख्यालय - नई दिल्ली में)
- उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत दिया था - अल्फ्रेड मार्शल ने
- 'न्यूनत्तम समर्थन मूल्य' संबंधित है- कृषि से
- न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करता है -कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP)
- खाद्यानों का न्यूनतम समर्थन मूल्य किस वर्ष शुरू किया गया था - 1964-65 में
- भारत में सबसे पहले चकबंदी कानून लागू की गई - 1920 ई॰ में (बड़ौदा में)
- चकबंदी के दो प्रकार है- ऐच्छिक व अनिवार्य
- ऐच्छिक चकबंदी की शुरूआत हुई थी - 1921 में (पंजाब से)
- अनिवार्य चकबंदी की शुरूआत हुई थी - 1928 में (मध्य प्रदेश से)
- देश में सर्वाधिक जोतों का प्रकार है- सीमांत
- सीमांत जोत का आकार है 1 हेक्टेयर से कम

- जोतों का आकार सबसे कम है केरल में
- जोतों का आकार सर्वाधिक है- राजस्थान में
- कृषि वर्ष माना जाता है- 1 जुलाई से 30 जन
- फसल बीमा योजना का शुभारंभ 1985 में
- कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी - राज समिति ने
- भारत की पहली कृषि जनगणना 1970-71
- भारत में 'राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना' किस वर्ष प्रारंभ हुई थी - 1999-2000 से
- कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य है - महाराष्ट्र
- भारत में कृषि को वित्त प्रदान करने वाली सर्वोच्च संस्था है - नावार्ड (NABARD)
- रबी फसल की बोआई अक्टूबर-नवम्बर
- खरीफ फसल की बोआई - जून-जुलाई
- रबी फसल है- गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों
- खरीफ फसल है चावल, बाजरा, मक्का
- जायद फसल -ककड़ी, तरबूजा, खीरा सब्जी
- भारत की मुख्य खाद्य फसल है चावल
- हरित क्रांति शब्द के सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता थे - डॉ॰ विलियम गॉड
- हरित क्रांति की शुरूआत - 1967-68 में
- भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता माना जाता है - एम॰ एस॰ स्वमीनाथन को
- हरित क्रांति के विश्व स्तरीय जनक माने जाते है - डॉ॰ नॉरमन बोरलॉग को
- हरित क्रांति से सबसे प्रभावित फसल गेहूँ
- हरित क्रांति के समय भारत का केन्द्रीय खाद्य एवं कृषि मंत्री थे - सी॰ एस॰ सुद्रमण्यम
- हरित क्रांति का जनक देश है फिलीपीन्स
- सर्वप्रथम हरित क्रांति आयी थी पंजाब में
- पीली क्रांति संबंधित है- तिलहन उत्पादन से
- भूरी क्रांति संबंधित है- उर्वरक उत्पादन से
- लाल क्रांति संबंधित है- मांस एवं टमाटर से गुलाबी क्रांति संबंधित है- झींगा उत्पादन से
- श्वेत क्रांति संबंधित है दूध उत्पादन से
- रजत क्रांति संबंधित है अंडा उत्पादन से
- बादामी क्रांति संबंधित है- मसाला उत्पादन से
- गोल क्रांति संबंधित है आलू उत्पादन से नीली क्रांति संबंधित है - मतस्य पालन से
- कृष्ण क्रांति संबंधित है - पेट्रोलियम से
- ब्राउन क्रांति संबंधित है गैर परंपरागत उर्जा से
- सुनहरी क्रांति संबंधित है फल उत्पादन से सभी क्रांतियों का सम्मिलन है- इन्द्रधनुषी क्रांति
- प्रत्यक्ष कर है- आयकर, सम्पति कर, निगम
- कर, मृत्यु कर, भू-राजस्व कर, उपहार कर अप्रत्यक्ष कर है- बिक्री कर, तट कर, उत्पाद
- कर, सीमा शुल्क केन्द्र सरकार लगाती है - आयकर, निगम
- कर, सम्पत्ति कर, धन कर, उपहार कर, सीमा शुल्क, कृषि धन पर कर
- राज्य सरकार द्वारा लगाया जाने वाला कर है - भू-राजस्व कर, कृषि आयकर, बिक्री कर, मनोरंजन कर, पथ कर, वाहन कर

- कर ढाँचे में सुधार के लिए गठित समिति थी
 चेलैया समिति (गठन-अगस्त, 1991 में)
- भारत में कर आगम का बड़ा स्रोत -निगम कर

निगम कर लगता है - कम्पनियों की आय पर

- भारत में पहली बार मूल्य वर्धित कर (VAT) लागू हुआ था - 2005 में, हरियाणा में
- संशोधित मूल्यवर्धित कर (MODVAT) संबंधित
 है उत्पाद कर से
- ♦ CENVAT संबंधित हैं-केन्द्रीय उत्पाद शूल्क से
- सर्विस टैक्स लेता है आयकर विभाग
- भारत में जीएसटी (GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स) लागू किया गया - 1 जुलाई, 2017
- ♦ GST है- अप्रत्यक्ष एवं गंतव्य आधारित कर
- ♦ GST सर्वप्रथम किस देश में लागू हुआ फ्रांस
- ♦ GST की चार दरें है 5, 12, 18 व 28%
 ♦ किस सिविधान संशोधन द्वारा भारत में जीएसटी
- लागू किया गया- 101वाँ संविधान संशोधन

 जीएसटी परिषद् की स्थापना- 12 Sep. 2016
- ♦ सेवा कर प्रारंभ किया गया 1994-95 में
- 'रेखा सिमिति' गठित की गयी थी
- अप्रत्यक्ष कर सुधार के लिए
- वांचू सिमिति सम्बंधित है- प्रत्यक्ष कर जाँच से
- वह स्थिति जिसमें वस्तुओं के मूल्य बढ़ते है तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है - मुद्रा स्फीति
- भारत में मुद्रा-स्फीति की माप की जाती है
- थोक-मूल्य-सूचकांक (WPI) द्वारा ♦ वर्तमान में थोक-मूल्य-सूचकांक का आधार
- वर्ष है 2011-12
- मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए RBI द्वारा प्रयुक्त शक्तिशाली साधन है- ब्याज दरें बढ़ाना
- ♦ मुद्रा स्फीति से हानि होता है- ऋणदाता को
- मुद्रा स्फीति से लाभ होता है ऋणी को
- 🕈 सर्वप्रथम मुद्रा का चलन हुआ 1542 में
- भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा (करेंसी) का प्रचलन हुआ था - 1862 में
- भारत ने दाशमिक/दशमलव मुद्रा प्रणाली को अपनाया गया - 1 अप्रैल, 1957 से
- भारत में मुद्रा की मीट्रिक प्रणाली को अपनाया गया - 1 अप्रैल, 1957 को
- विश्व में मुद्रा की मीट्रिक प्रणाली सर्वप्रथम अपनायी गयी थी - 1790 में (फ्रांस में)
- मुद्रा-अवस्फीति वह स्थिति है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य घटता है तथा मुद्रा का मुल्य बढता है
- स्टैगफ्लेशन है मंदी के साथ मुद्रा स्फीति
- भारत में कर्मचारियों के महँगाई भत्ते का निर्घारण किस आधार पर होता है- उपभोक्ता कीमत सचकांक
- अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य
 को घटना क्या कहलाता है अवमुल्यन
- मुद्रा अवमूल्यन का उद्देश्य होता है निर्यात
 को बढ़ावा तथा आयात को कम करना
- भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन हुआ है
 नीन बार (1949, 1966 तथा 1991 में)

- वह मुद्रा जिसमें शीघ्र प्रवास/पलायन की प्रवृत्ति होती है कहलाती है - हॉट/गर्म मनी
- रूपये को चालू खातों में पूर्ण परिवर्तनीय घोषित किया गया - 19 अगस्त, 1994 को
- यूरो मुद्रा का प्रारंभ 11 देशों में प्रारंभ हुआ था
 1 जनवरी, 1999 में
- वर्तमान में यूरो मुद्रा को अपनाने वाले राष्ट्रों की संख्या है- 19 (19वाँ देश-लिथुआनिया)
- सबसे महँगी मुद्रा इंगलैंड की पाउंड स्टर्लिंग
- वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति माँग की अपेक्षा कम हो, कहलाती है - हाई करेंसी
- वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति माँग की अपेक्षा
 अधिक हो, कहलाती है सॉफ्ट करेंसी
- 'ग्रेशम का नियम' संबंधित है
 - मुद्रा के प्रचलन से
- सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है - विमुद्रीकरण
- भारत में अबतक कितनी बार विमुद्रीकरण हुआ है - तीन बार (1946, 1978, 2016)
- भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया
 1993-94 के बजट में
- 'बाजार के िनयम' के प्रतिपादक जे॰ बी॰ से
- हवाला है मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार
- 'मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है' यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की - क्रोडमर ने
- 'ऐच्छिक मुद्रा' कहलाता है
 साख मुद्रा
- 'कानूनी मुद्रा' को कहा जाता है फ्लैट मनी
- 'प्लास्टिक मनी' कहलाता है क्रेडिट कार्ड
 'ब्लैक मनी' का अर्थ है अघोषित धन
- 'ब्लैक मनी' का अर्थ है अघोषित धन
 'स्मार्ट मनी' का अर्थ है क्रेडिट कार्ड से
- मुद्रा पूर्ति में विस्तृत मुद्रा कहलाता है M3
- भारत का सबसे अधिक विदेशी मुद्रा व्यय होता है - कच्चा तेल के आयात पर
- भारत सर्वाधिक आयात करता है चीन से
- भारत सर्वाधिक निर्यात करता है-अमेरिका को
- भारतीय निर्यात का सबसे महत्वपूर्ण मद है
 पेट्रोलियम उत्पाद
- भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है
 अमेरिका
- मौद्रिक व्यवस्था की इकाई रूपया है।
- ♦ एक रूपये के नोट पर हस्ताक्षर होते है
- वित्त सचिव का
- एक रूपये से अधिक के सभी मूल्य के नोटों
 पर हस्ताक्षर होते हैं RBI के गवर्नर का
- ♦ RBI द्वारा निर्गत सभी नोटों पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता - 17
- ♦ एक रूपये के नोट व सिक्के जारी किए जाते
 है भारत सरकार ∕वित्त मंत्रालय द्वारा
- भारत में वित्तीय घाटे का मौद्रिकरण प्राप्त किया जाता है - सरकार द्वारा ऋण लेकर
- जिस बाजार से ऋण के रूप में धन प्राप्त किया
 जा सकता है, कहलाता है मुद्रा बाजार

- 'गिल्ट एज्ड बाजार' संबंधित है सरकारी प्रतिभृतियों के व्यापार∕क्रय-विक्रय से
- भारत सर्वाधिक आयात करता है
 - तेल एवं पेट्रोलियम पदार्थ का
- निर्यातकों एवं आयातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है - निर्यात-आयात बैंक
- निर्यात-आयात बैंक (Exim-Bank) की स्थापना हुई थी - 1 जनवरी, 1982 में
- भारत में जीवन बीमा देन है ब्रिटेन की
- मल्होत्रा समिति का गठन किस प्रयोजन से किया गया था - बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए सिफारिश देने के लिए
- दीर्घकालिक वित्त उपलब्ध कराने वाली संस्था है - UTI, LIC, GIC
- भारतीय जीवन बीमा (LIC) की स्थापना हुई
 थी 1 सितम्बर, 1956 को
- भारत के सामान्य बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण हुआ था - 1971 में
- सामान्य बीमा निगम (GIC) की स्थापना हुई थी
 1972 में
- ♦ बीमा क्षेत्र का नियमन करती है IRDA
- IRDA (बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण)
 का गठन किया गया था 19 अप्रैल, 2000
 को (मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर)
- सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संगठन है UTI
- भारतीय यूनिट ट्रस्ट (UTI) की स्थापना हुई थी
 -1 फरवरी, 1964 को (मुख्यालय-मुम्बई)
- भारत का पहला म्युचुअल फण्ड यू॰ एस॰-64
- भारत का प्रतिभूति मुद्रणालय, सिक्योरिटी प्रिटिंग प्रेस तथा बैंक नोट प्रेस स्थित है - क्रमशः नासिक, हैदराबाद तथा देवास में
- भारत में करेंसी नोटों का मुद्रण एवं आपूर्ति की जाती है - सिक्यूरिटी प्रेस, नासिक द्वारा
- भारत में सिक्का बनाया जाता है मुम्बई,
 कोलकाता, हैदराबाद एवं नोएडा में
- ♦ सहकारी सिमितियों का ढाँचा है- त्रि-स्तरीय
 ♦ नकदी में प्राप्त मजदरी है- मौदिक मजदरी
- भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष पहली बार स्वीकृत हुआ - वर्ष 1948 में
- पूँजी साधन का प्रतिफल होता है ब्याज
- अार्थिक संवृद्धि का अर्थ- उत्पादन में वृद्धि
- रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल, 1935
 को (हिल्टन यंग आयोग के सिफारिश पर)
- रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी,
 1949 को (गवर्नर-सी. डी. देखमुख)
- रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर- ओसबार्न स्मिथ
- रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर थे
 सी. डी. देखमुख
- भारतीय रिजर्व बैंक की प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर थी - के. जे. उदेशी
- भारतीय रिजर्व बैंक में होते है
 - 1 गवर्नर तथा 4 डिप्टी गवर्नर
- रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष-1 जुलाई से 30 जून

- ♦ इम्मीरियल बैंक ऑफ इंडिया नाम बदलकर 1 जुलाई, 1955 को रखा गया था - SBI
- देश का बड़ा सार्वजनिक/व्यवसायिक बैंक है
 भारतीय स्टेट बैंक (SBI)
- SBI बैंक की स्थापना 1 जुलाई, 1955
 (गोरवाला समिति की संस्तुति पर)
- सर्वप्रथम 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण
 किया गया था 19 जुलाई, 1969 को
- दूसरी बार 6 अन्य व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया −15 अप्रैल, 1980
- भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की संस्तुति प्रस्तुत की थी - हजारी समिति ने
- नोटो का निर्गमन करता है- RBI(1 रूपये का नोट एवं सिक्कों को छोड़कर)
- वर्तमान में नोट निर्गमन हेतु अपनायी जाने वाली प्रणाली है - न्युनत्तम कोष प्रणाली
- नोट निर्गमन की न्यूनतम कोष प्रणाली अपनाया गया था - अक्टूबर, 1956 में
- RBI के पास हर समय न्यूनतम कितने मूल्य का स्वर्णकोष रहना चाहिए-115 करोड़ रूपये
- फेडरल रिजर्व केन्द्रीय बैंक है -अमेरिका का
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) को प्रायोजित करता है - राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंक
- ♦ RRBs की स्थापना 2 अक्टूबर, 1975
- ♦ रिजर्व बैंक ऋण प्रदान करता है-90 दिन का
- भारत का प्रथम बैंक बैंक ऑफ हिन्दुस्तान
- वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12
- बैंकिंग लोकपाल योजना पहली बार भारत में शुरू की गई - 1995 में (संशोधन-2002)
- वर्तमान में बैंकिंग लोकपाल (ओम्बुड्समैन)
 योजना प्रभावी है 2006 से
- बैंकिंग लोकपाल का कार्य है बैंक ग्राहकों को बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं से संबंधित शिकायतों का समाधान करना
- 'क्रेडिट कार्ड' जारी करने वाला पहला बैंक
 सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
- 'प्रीपेड कार्ड' जारी करने वाला पहला बैंक
 -ओरिऐंटल वैंक ऑफ कॉमर्स, 2003 में
- ∳ 'इंटरनेट बैंकिंग' शुरू करने वाला पहला बैंक
 FICICI (स्थापना-1994 में)
- किसान क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ -1998 में
- मारत में ATM सेवा शुरू करने वाला पहला
 बैंक है HSBC (1987 में)
- देश का प्रथम तैरता ATM स्थापित किया गया
 कोच्चि में (SBI द्वारा)
- केन्द्रीय बैंकिंग जाँच संमिति की स्थापना हुई
 थी 1931 ई. को
- नरसिंहम् समिति संबंधित है
 वैंकिंग संरचना सुधार से
- गोईपोरिया समिति संबंधित है
 वैंक में ग्राहक सेवा सुधार से
- देश का पहला मोबाईल बैंक है
 लक्ष्मी वाहनी बैंक (मध्य प्रदेश)
- यू॰ टी॰ आई॰ बैंक वर्तमान नाम है एक्सिस

- बैंक (30 जुलाई, 2007 से)
- 'भारतीय औद्योगिक विकास बैंक' (IDBI) की स्थापना की गई थी- 1 फरवरी, 1964 को
- अल्पकालिक सरकारी प्रतिभृति कहलाता है
 − ट्रेजरी बिल (Treasury Bills)
- भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते है RBI द्वारा
- वर्तमान में RBI कितने दिनों की ट्रेजरी बिल्स निर्गमित करता है - 91 एवं 364 दिन की
- ट्रेजरी बिल्स की न्यूनतम राशि होती है 25000 रूपया तथा इसी गुणक में
- एडहॉक ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त किया
 गया 31 मार्च, 1997 को (शुरू-1955)
- भारत में मौद्रिक नीति जारी करता है- मौद्रिक नीति समीति (अध्यक्ष-RBI के गवर्नर)
- ◆ RBI मौद्रिक नीति की समीक्षा करता है
 प्रति दो माह पर
- मौद्रिक नीति के प्रमुख उपकरण है

 रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR
- जिस दर पर बैंक रिजर्व बैंक से उधा√नकदी
 ऋण प्राप्त करते है, कहलाता है रेपो दर
- वह दर जिसपर, RBI अन्य बैंकों से ऋण लेती है, कहलाता है - रिवर्स रेपो दर
- बैंक, RBI द्वारा निर्धारित राशि को जब नकद
 के रूप में RBI के पास जामा करें तो वह
 कहलाता है- नगद आरक्षित अनुपात (CRR)
- बैंक, RBI द्वारा निर्धारित राशि को जब प्रतिभृति के रूप में अपने पास रखता है तो वह कहलाता है- वैधानिक तरलता दर (SLR)
- RBI जिस दर पर वाणिज्यिक बैंकों को ऋण उपलब्ध कराता है, वह कहलाता है - वैंक दर
- ♦ NEFT और RTGS साधन है-मुद्रा अंतरण के
- ♦ NEFT का पूर्ण रूप है
 - National Electronic Fund Transfer
- ♦ RTGS का पूर्ण रूप है
 - Real Time Gross Settlement
- ♦ IFSC का पूर्ण रूप है
 - Indian Financial System Code
- भारतीय बैंकों का सर्वाधिक शाखाएँ यूके में
- ♦ सहकारी बैंक का गठन होता है -तीन स्तर पर
- भारत में सहकारी बैंकों की शुरूआत 1904
 मानसून का जुआ कहलाता है भारतीय बजट
- चाटे का बजट कहलाता है
 - जब सरकारी आय, व्यय से कम हो
- आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है
 वित्त मंत्रालय द्वारा (लोकसभा में)
- ♦ शून्य आधारित बजट का अर्थ है- हर बार बिल्कुल नये सिरे से बजट तैयार करना
- शून्य आधारित बजट देन है- अमेरिका की
- भारत में शून्य आधारित बजट को किस वर्ष के वार्षिक बजट में अपनाया गया- 1987-88
- 'शून्य आधारित बजट' की अवधारणा के प्रतिपादक थे - पी॰ ए॰ पायर
- कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर कहलाता है → बजटीय घाटा

- अर्थशास्त्र में निवेश की अर्थ होता है
 श्रेयरों की खरीदारी
- विश्व का प्रथम नकदी रहित अर्थव्यवस्था वाला देश है - स्वीडन
- ∳ 'बिग पुश' सिद्धांत दिया था रॉडन ने
- ठपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (COPRA) कब पारित किया गया था − वर्ष 1986
- ◆ 'उपभोक्ता के बचत का सिद्धांत' दिया था
 अल्फ्रेड मार्शल ने
- पूँजी-बाजार से आशय है- शेयर बाजार से
- भारत का पहला व सबसे पुराना 'बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE)' की स्थापना - 1875 में
- BSE एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में परिवर्तित हुआ - 19 अगस्त, 2005 से
- दलाल स्ट्रीट स्थित है मुम्बई में
- ♦ BSE का सूचकांक है- सेन्सेक्स (SENSEX)
- राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज (NSE) की स्थापना -1992 में फेरवानी समिति के सिफारिश पर
- ♦ NSE का प्रमुख प्रवर्तक है IDBI
- ♦ NSE का मुख्यालय है- वर्ली (मुम्बई) में
- ♦ NSE का सूचकांक है- निफ्टी (NIFTY)
- तेजडिया (बुल) एवं मंदिंड्या (बियर) संबंधित
 है स्टॉक मार्केट (शेयर बाजार) से
- भारत में स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या है-23
- ♦ BSE के 30 शेयरों वाला 'संवेदी सूचकांक'
 का आधार वर्ष है 1978-79
- ♦ BSE के 100 शेयरों वाला 'राष्ट्रीय सूचकांक'
 का आधार वर्ष है 1983-84
- ♦ NSE के 50 शेयरों का सूचकांक है NIFTY
- 'नास्डैक' शेयर सूचकांक है अमेरिका का
- 'डो-जोन्स' शेयर सूचकांक है- न्यूयार्क का
- 'फ्रैंकफर्ट' शेयर सूचकांक है जर्मनी का
- ∳ 'निक्की' शेयर सूचकांक है जापान का
- भारत में स्टॉक एक्सचेंजों का नियमन करने वाली बॉडी है - SEBI (मुख्यालय-मुम्बई)
- भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य करता है- सेवी (SEBI)
- भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI)
 की स्थापना हुई थी- 12 अप्रैल, 1988 में (एस॰ ए॰ दवे समिति की अनुशंसा पर)
- सेबी को वैधानिक दुर्जा 30 जनवरी, 1992
- विश्व का पहला संगठित शेयर बाजार स्थापित
 किया गया था 1962 में, एम्सटर्डम में
- ♦ भारतीय खाद्य निगम/FCI की स्थापना 1965
- भारत में प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना हुई थी - 1920 में, झांग (पंजाब) में
- भूमि विकास बैंक का प्रमुख कार्य है दीर्घ -कालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना
- विश्व व्यापी आर्थिक मंदी आयी थी-1929 में
- खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) की स्थापना
 10 अक्टूबर, 1945 को (इटली में)
- ♦ विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ-Special Economic Zone) नीति घोषित की गई थी 2000 में
- ♦ SEZ एक्ट पारित किया गया 2005 ई॰ में

- ♦ पहला SEZ विकसित किया गया कांडला में
- माल्थ्स सिद्धांत संबंधित है जनसंख्या से
- मीरा सेठ समिति संबंधित है हथकरघा से
- सत्यम् समिति संबंधित है वस्त्र नीति से
- महाजन समिति का संबंध है चीनी उद्योग से
- ज्ञान प्रकाश समिति चीनी घोटाले से
- मृंदरराजन समिति संबंधित है- पेट्रोलियम से
- हजारी समिति औद्योगिक नीति से
- ◆ दत्त समिति औद्योगिक लाईसेंस से
- मिर्धा समिति संबंधित है
 - सहकारिता आन्दोलन से
- भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) की स्थापना - 2 अप्रैल, 1990
- ♦ SIDBI का मुख्यालय है लखनऊ में
- → आबिद हुसैन समिति का सम्बंध किससे है
 लघु उद्योग क्षेत्र से
- मालेगाम समिति का गठन किस क्षेत्र से संबंधित है - प्राथमिक पुँजी बाजार
- पहला राज्य वित्त निगम स्थापित किया गया
 1953 में (पंजाब में)
- इलेक्ट्रॉनिक समान की गुणवता प्रदर्शित करता
 है ISI मार्क, 1955 से भारत में प्रभावी है
- भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) अस्तित्व में आया
 1 अप्रैल, 1987 को (मुख्यालय दिल्ली)
- हॉलमार्क संबंधित है स्वर्ण-आभूषण से
- 'हॉलमार्क' व्यवस्था लागू है 2002 से (सोना पर) तथा 2005 से (चाँदी पर)
- पेटेंट अधिनियम सर्वप्रथम पारित 1970 में
- ट्रेडमार्क अधिनियम प्रभावी है
- 15 सितम्बर, 2003 से
- इकोमार्क संबंधित है पर्यावरण से
- कृषि वस्तुओं की गुणवता को प्रदर्शित करता
 है एगमार्क (वर्ष 1986 से प्रभवी है)
- केन्द्रीय एगमार्क प्रयोगशाला है नागपुर में
- शीतल पेय, साँस आदि के प्रमाणन के लिए प्रयुक्त चिह्न है - एफ. पी. ओ. (FPO)
- श्वेत वस्तुएँ के अन्तर्गत शामिल है फ्रिज, जनरेटर, वाशिंग मशीन (विजली की वस्तुएँ)
- क्रिसिल (CRISIL) है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी
- ◆ CRISIL का पूर्ण रूप है Credit Rating Information Service of India Ltd.
- भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना प्रारंभ की गई थी - 1952 में
- राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है
 हैदराबाद (स्थापना 1977 ई॰) में
- कर्जा संकट भारत में सबसे पहले कब महसूसे
 किया गया 1973 में
- ♦ सेल (SAIL) की स्थापना 1974 में
- 'सफंद सोना' कहा जाता है कपास को
- 'हरा सोना' किसे कहा जाता है चाय को
- 'स्वर्ण द्रव' कहा जाता है पेट्रोलियम को
- स्पेशल-301 तथा सुपर-301 क्या हैं अमरीकी व्यापार संरक्षण की नीतियाँ है

- किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया निवेश कहलाता है -प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ∕FDI-Foreign Direct Envestment
- भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का सबसे बड़ स्रोत देश है – सिंगाप्र
- भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार किसके साथ है – संयुक्त राज्य अमेरिका
- ◆ GATT की स्थापना हुई थी 1948 ई॰ में
- GATT का स्थान WTO ने लिया था 1 जनवरी, 1995 से (मुख्यालय जेनेवा)
- ♦ WTO के प्रथम अध्यक्ष पीटर सदरलैंण्ड
- विश्व व्यापार संगठन (WTO) की सदस्य संख्या
 है 164 (164वाँ अफगानिस्तान)
- विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1945 में
- विश्व बैंक का मुख्यालय- वाशिंगटन डी.सी.
- विश्व बैंक का अन्य नाम पुनर्निमाण एवं विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय बैंक
- विश्व बैंक ऋण देता है दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन दोनों
- विश्व बैंक की 'उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की' कहा जाता है - अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (IDA) को
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की स्थापना-दिसम्बर, 1945 में (मुख्या, -वाशिंगटन डीसी)
- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी कहा जाता है
 अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) को
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) किस सम्मेलन की देन हैं - ब्रेटनबुड्स सम्मेलन की
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किन देशों को ऋण प्रदान करता है - केवल सदस्य देशों को
- किस दशक में जनसंख्या वृद्धि-दर ऋणात्मक
 थी 1911 से 21
- जन्म दर व्यक्त किया जाता है प्रति हजार पर
- 🔷 राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन 2004 में
- भुगतान संतुलन में निहित होता है
 दुश्य-अदुश्य व्यापार एवं ऋण
- क्टेंशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (FERA) पारित किया गया था - 1973 में (विदेशी निवेश एवं व्यापार को सगम बनाने हेत)
- ♦ FERA की जगह FEMA (विदेशी मुद्रा प्रबन्धन अधिनियम) लागू हुआ - 1999 में
- 'इंडिया इज फॉर सेल' नामक पुस्तक किसने लिखी है - चित्रा सब्बह्मण्यम ने
- मोहन धारिया समिति का संबंध किससे है
 वाटरशेड विकास से
- ईश्वरन समिति का संबंध है
 - वाटरशेड विकास में प्रशिक्षण से
- ♦ डेविडेंट (Divident) क्या होता है
- कम्पनियों से शेयरों पर प्राप्त लाभांश
- ∳ 'कूटीर ज्योति कार्यक्रम' का सम्बंध है
 ग्रामीण विद्यतीकरण से
- 'बैल्यू एण्ड कैपिटल' नामक पुस्तक किसकी रचना है - हिक्स की
- 'पेपर गोल्ड' कहलाता है एस.डी.आर.

- 'इंडिया ब्रांड ईक्विटी फण्ड' की स्थापना किस वर्ष हुई है - 1996 में
- 'आशा योजना' संबंधित है
- सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से
- राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा एवं राजस्व घाटे में बड़ा कौन-सा है - राजकोषीय घाटा
- समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP)
 किस वर्ष प्रारंभ किया गया 1978-79 में
- नई आर्थिक नीति की शुरूआत हुई 24 जुलाई, 1991 को डॉ. मनमोहन सिंह टारा
- नई औद्योगिक नीति 1991 की घोषणा की गई
 24 जुलाई, 1991 को नरसिम्हा राव द्वारा
- ♦ NGO का आशय है गैर-सरकारी संगठन
- सार्वजनिक उद्यमों को वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करने हेतु दर्जा दिया जाता है - महारत्न, नवरत्न एवं मिनीरत्न का
- देश में महारत्न कम्पनियों की संख्या है-11
- देश में नवरल कम्पनियों की संख्या है- 13
- नवरल की अवधारणा किस वर्ष के केन्द्रीय बजट में पेश की गई थी - वर्ष 1997-98
- कम्पनियों को नवरल का दर्जा दिया जाता है
 केन्द्रीय लोक उद्यम विभाग द्वारा
- महारल दर्जे के सृजन का निर्णय लिया गया
 21 दिसम्बर, 2009 को
- मिनीरत्न योजना का शुभारंम 1977 में
- भारत का सबसे बड़ा उद्योग है
 - सूती वस्त्र उद्योग
- योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य है
 चयनित आधारभत उद्योग
- कोर सेक्टर के 8 आधारभूत उद्योग है -इस्पात, सीमेंट, उर्वरक, खनिज तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद व विद्यत
- ♦ NTPC की स्थापना हुई थी 1975 में
- तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग (ONGC) की
 स्थापना हुई थी 1956 ई॰ में
- 'गोल्डेन हैण्ड शेक स्कीम' संबंधित है
 स्वैच्छिक सेवानिवृति से
- ♦ TDS Tax Deducted at Sourse
- ◆ EMI Equated Monthly Installment
 ◆ SIP Systematic Investment Plan
- ♦ KYC Know Your Customer
- ECS Electronic Clearance Service
 PAN
- ◆ PAN Permanent Account Number
 ◆ CRY Child Rights and You
- ♦ CBS Core Banking Solutions
- ♦ SEBI का पूर्णरूप है Securities and Exchange Board of India
- ♦ NABARD কা মুর্ণাৰুপ National Bank for Agriculture and Rural Development
- भारतीय सांख्यिकीय संस्थान कोलकाता में
 एशियाई विकास बैंक (ADB) की स्थापना
- हुई थी 1966 में (मुख्यालय-मनीला)
- भुगतान संतुलन (BOP) पद संदर्भित करता है
 आयात तथा निर्यात के मध्य अंतर को